



मंत्रालयों और विभागों की वर्षात समीक्षा

(भाग-1)

(पूरक डॉक्यूमेंट)

विषय-सूची

1. रक्षा मंत्रालय (Ministry Of Defence)	3
2. विधि और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law & Justice).....	6
3. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics & Information Technology)	6
4. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change).....	7
5. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) {Department For Promotion of Industry and Internal Trade (Ministry of Commerce & Industry)}	8
6. वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce).....	10
7. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution)	11
8. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment)	13
9. भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) {Department of Land Resources (Ministry of Rural Development)} ..	14
10. पशुपालन एवं डेयरी विभाग (मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय) {Department of Animal Husbandry & Dairying (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying)}.....	14
11. मत्स्य पालन विभाग (मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय) {Department of Fisheries (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying)}	15
12. वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textile)	16
13. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation).....	17
14. भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries).....	17
15. पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism).....	18
16. नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation)	19

17. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs).....	20
18. खेल विभाग (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय) {Department of Sports (Ministry of Youth Affairs And Sports)}	21
19. संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture).....	22

नोट: इस डॉक्यूमेंट में वर्ष 2023 के संदर्भ में प्रेस सूचना ब्यूरो पर प्रकाशित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों की वर्षांत समीक्षा का संक्षिप्त ब्योरा प्रदान किया गया है। इसमें विभिन्न सरकारी क्षेत्रों की पहलों, प्रगति और उपलब्धियों के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी प्रदान की गई है। इस डॉक्यूमेंट से UPSC के आगामी इंटरव्यू की तैयारी के लिए तेजी से रिवीजन करने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही, इसका उपयोग करके अभ्यर्थी अपने नोट्स को और बेहतर बना सकते हैं।

भाग-1 इसमें भारत सरकार के 19 मंत्रालयों/ विभागों की वर्षांत समीक्षाएं शामिल हैं, जैसा कि विषय-सूची में भी दिया गया है। भारत सरकार के शेष मंत्रालयों/ विभागों की वर्षांत समीक्षा का संक्षिप्त ब्योरा भाग II में प्रदान किया जाएगा।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence)

विषय	पहल/ प्रगति/ उपलब्धियां
रक्षा क्षेत्रक में आत्मनिर्भरता	- रक्षा मंत्रालय ने सकारात्मक स्वदेशीकरण (Positive Indigenisation) की पांचवीं सूची को जारी किया। इसमें रक्षा क्षेत्रक से जुड़ी 98 वस्तुओं को शामिल किया गया है। - स्मरणीय तथ्य (2022-23): - रक्षा उपकरणों के उत्पादन का मूल्य एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा। - रक्षा निर्यात 16,000 करोड़ रुपये के मूल्य को पार कर गया। - रक्षा क्षेत्रक से संबंधित पूंजीगत खरीद के बजट का 75% घरेलू उद्योगों के लिए आवंटित किया गया था। - वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कुल बजट का 13.18% रक्षा क्षेत्रक को आवंटित किया गया। - प्रमुख विकास - हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) की नई हेलीकॉप्टर फैक्ट्री की स्थापना तुमकुरु (कर्नाटक) में की गई। यहां पर HAL, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर (LUHs) का उत्पादन करेगी। - HAL ने तेजस लड़ाकू विमान को वायुसेना को सौंप दिया है। - रक्षा उत्पादन विभाग - सृजन पोर्टल (Srijan Portal): यह पोर्टल रक्षा हथियारों/ उपकरणों के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए MSMEs, स्टार्ट-अप, उद्योगों को सहायता प्रदान करेगा। - अस्त्र (ASTRA): स्वदेशी 'बियॉन्ड विजुअल रेंज (BVR)' वाली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल 'अस्त्र' का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। - ATMAS: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)¹ द्वारा विकसित स्वदेशी ATMAS (एयर टैफिक मैनेजमेंट ऑटोमेशन सिस्टम) का परिचालन शुरू हुआ। - वरुणास्त्र: भारतीय नौसेना ने एंटी-सबमरीन टॉरपीडो "वरुणास्त्र" का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित भारी वजन वाला टारपीडो है। इसे जहाज से लॉन्च किया गया। - BEL द्वारा विकसित I-ATS (इंडिजेनस-ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन) प्रणाली को औपचारिक रूप से रेड लाइन पर शुरू किया गया। - MIDHANI (मिश्रा धातु निगम लिमिटेड): MIDHANI ने स्वदेशी रूप से SNI C276 शीट का विकास किया है। यह एक संक्षारण-रोधी (Corrosion-resistant) सामग्री है।
रक्षा उपकरणों/ हथियारों की खरीद	- Su-30 MKI लड़ाकू विमानों को अपग्रेड किया जा रहा है। 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट की खरीद के लिए फ्रांस से समझौता किया जा रहा है। 31 MQ-9B (16 स्काई गार्जियन और 15 सी-गार्जियन) हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंज्योरेंस (HALE) को संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात किया जाएगा।
सीमाओं पर अवसंरचना का विकास	- सीमा सड़क संगठन (BRO)² ने अलग-अलग अवसंरचना परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित की। इनमें नेचिफू सुरंग, सियोम ब्रिज, शिंकू ला और सेला ला ब्रिज (अरुणाचल प्रदेश) और कंडी सुरंग (जम्मू-कश्मीर) शामिल हैं। - BRO, निम्नलिखित प्रयासों के माध्यम से हरित पहलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है:- - ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता मानदंडों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, और

¹ Airports Authority of India

² Border Roads Organisation

	○ अनौपचारिक वेतनभोगी मजदूरों (CPLs)³ के रहने के लिए नेट कार्बन तटस्थ आवासों का निर्माण किया जा रहा है।
थल सेना	• पूर्वोत्तर क्षेत्र में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम (AFSPA-1958) के तहत अशांत क्षेत्रों का दायरा कम किया गया है। • पूंजीगत अनुबंधों, IDEX (इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस) के जरिए तथा 5G/6G, AI की क्षमताओं के उपयोग से सेना का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। • नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, पी.एम. गति शक्ति, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (iGOT) कर्मयोगी प्लेटफॉर्म द्वारा विभिन्न प्रणालियों और प्रक्रियाओं को एकीकृत किया जा रहा है; BISAG-N के माध्यम से अतिरिक्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है तथा 'सही समय पर सही व्यक्ति को सही पेंशन' सुनिश्चित करने के लिए स्पर्श (SPARSH) को अपनाया गया है। • लैंगिक समानता: भारतीय सेना में महिलाओं को जूनियर कमीशंड ऑफीसर (JCOs) के रूप में शामिल किया जा रहा है। अब महिला अधिकारियों को कमांड ऑफ यूनिट की जिम्मेदारी दी गई है। • संयुक्त सैन्य अभ्यासों के माध्यम से रक्षा संबंधी कूटनीति को मजबूत किया जा रहा है। इसके अलावा इंडो-पैसिफिक आर्मीज़ मैनेजमेंट सेमिनार (IPAMS) एवं इंडो-पैसिफिक आर्मीज़ चीफ्स कॉन्फ्रेंस (IPACC) आदि के द्वारा इंडो-पैसिफिक में मौजूद आम चुनौतियों से निपटने के लिए सैन्य सहयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। • भारतीय सेना मिशन अमृत सरोवर, विद्यांजलि आदि योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में भी अपना योगदान दे रही है।
भारतीय नौसेना	• भारतीय नौसेना मेक स्कीम, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड और IDEX जैसी पहलों के द्वारा रक्षा क्षेत्र में 2047 तक पूरी तरह से आत्मनिर्भर और स्वदेशी बनने के लिए प्रतिबद्ध है। • INS वागिर को नौसेना बड़े में शामिल किया गया। संध्याक (Sandhayak) नामक एक सर्वेक्षण पोत को दिसंबर 2023 में नौसेना को सौंप दिया गया। • विंध्यगिरी, संशोधक, महेंद्रगिरि जैसे युद्धपोतों को लॉन्च किया गया। • भारतीय नौसेना लैंगिक समानता सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय कर रही है। नौसेना की सभी शाखाओं में महिलाओं को शामिल किया जा रहा है, महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया जा रहा है, महिला अग्निवीरों की भर्ती की जा रही है एवं सेना में जेंडर तटस्थ भाषा को अपनाने पर बल दिया जा रहा है आदि। • भारतीय नौसेना ने अलग-अलग देशों के साथ ट्रोपेक्स, एम्फेक्स, मालाबार, सी ड्रैगन जैसे अभ्यास आयोजित किए।
भारतीय वायु सेना (IAF)	• IAF ने प्रोजेक्ट SAMAR (Surface to Air Missile for Assured Retaliation) के अंतर्गत हवा-से-हवा में मिसाइल दागने के लिए जमीन स्थित प्लेटफॉर्म के प्रोटोटाइप के स्वदेशी संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण पूरा किया। • IAF ने वीर गार्जियन, पैसेक्स (PASSEX), डेजर्ट फ्लैग, कोबरा वॉरियर, कोप इंडिया, ओरियन जैसे अभ्यासों में भाग लिया। • अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संकट के समय आवश्यक मानवीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए IAF ने कई महत्वपूर्ण अभियान चलाए। ये अभियान हैं: ○ ऑपरेशन दोस्त: तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के दौरान मानवीय सहायता, ○ ऑपरेशन कावेरी: सूडान गृहयुद्ध के दौरान भारतीय और विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए, और

³ Casual Paid Labourers

	○ ऑपरेशन अजय: इजरायल-हमास संघर्ष के दौरान। ○ उपर्युक्त के अलावा गोवा, तमिलनाडु, लद्दाख में भी इसी तरह के ऑपरेशन चलाए गए। • IAF, राष्ट्र निर्माण एवं देश की आंतरिक सुरक्षा में भी सहायता करती रही है। उदाहरण के लिए; भारत में आयोजित G-20 बैठकों के बेहतर तरीके से संचालन में मदद से लेकर, मणिपुर और हरियाणा में आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में IAF ने काफी मदद की। • एयरो इंडिया 23 और भारत ड्रोन शक्ति 2023 आयोजनों के द्वारा भारतीय वायुसेना की ताकत का प्रदर्शन किया गया। • IAF के नए ध्वज (Ensign) का अनावरण किया गया। इस ध्वज के निचले दाएं कैंटन में IAF 'ट्राई कलर राउंडेल' है। ○ IAF क्रेस्ट के शीर्ष पर राष्ट्रीय चिह्न अशोक स्तंभ और उसके नीचे देवनागरी में "सत्यमेव जयते" अंकित है। • e-MMS (ई-रखरखाव प्रबंधन प्रणाली) की मदद से अलग-अलग सेवाओं का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। • IAF अपनी ऑपरेशनल पहुंच का विस्तार करने के लिए न्योमा (लद्दाख) में एयरफील्ड का विकास कर रहा है।
भारतीय तटरक्षक	• डिजिटल कोस्ट गार्ड परियोजना के तहत एक एडवांस डेटा सेंटर का निर्माण किया जा रहा है, मजबूत आपदा रिकवरी डेटा सेंटर की स्थापना की जा रही है।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)	• स्वदेशी प्रौद्योगिकी क्रूज मिसाइल (ITCM)⁴: यह एक नई पीढ़ी की 'लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल' है, जिसे भूमि और समुद्री प्लेटफॉर्म से लॉन्च करने के लिए विकसित किया जा रहा है। • हल्के लड़ाकू विमान (LCA)⁵ तेजस से ASTRA BVRAAM मिसाइल का पहला परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। • तीसरी पीढ़ी की मैन-पोर्टेबल एंटी-टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह 'फायर एंड फॉरगेट' और 'टॉप अटैक' क्षमताओं से युक्त है। • ऑटोनॉमस फ्लाईंग विंग टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर ने सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण पूरा किया। • एयर ड्रॉपेबल कंटेनर (ADC-150) को नौसेना की ऑपरेशनल लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 150 किलोग्राम की पेलोड क्षमता के साथ डिजाइन और विकसित किया गया है। • गगनयान के लिए क्रू मॉड्यूल पैराशूट सिस्टम का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया। • DRDO द्वारा धारित पेटेंट्स तक निःशुल्क पहुंच की अनुमति देकर भारतीय उद्योगों की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ावा दिया जा रहा है।
राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) और सैनिक स्कूल	NCC • विश्व में सबसे बड़े वर्दीधारी युवा संगठन NCC की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई। • NCC इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर को 'एंड्री टू एग्जिट मॉडल' पर डिजाइन किया गया है। यह "एक बार कैडेट हमेशा कैडेट⁶" के दृष्टिकोण से प्रेरित है। यह सॉफ्टवेयर NCC में नामांकन से लेकर इससे निकलने तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए विकसित किया गया है। सैनिक स्कूल • राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित किए जाएंगे।

⁴ Indigenous Technology Cruise Missile

⁵ Light Combat Aircraft

⁶ Once a Cadet always a Cadet

2. विधि और न्याय मंत्रालय (Ministry of Law & Justice)

संसद द्वारा पारित महत्वपूर्ण विधेयक/नए अधिनियम	- मध्यस्थता अधिनियम, 2023 (Mediation Act, 2023): यह कानून मध्यस्थता, विशेषकर संस्थागत मध्यस्थता के लिए विधायी फ्रेमवर्क प्रदान करता है। - भारतीय मध्यस्थता परिषद (ACI)⁷: 12 अक्टूबर, 2023 को ACI से संबंधित मध्यस्थता और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 10 को अधिसूचित किया गया। - नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (संशोधन) अधिनियम, 2022 को 27 जनवरी 2023 से लागू किया गया। इस संशोधन अधिनियम के द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (NDIAC)⁸ का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र (IIAC)⁹ कर दिया गया। - अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 2023: इसने विधि व्यवसायी अधिनियम, 1879 की कुछ धाराओं को निरस्त कर दिया।
वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) ¹⁰ पर मार्गदर्शिका	संविधान दिवस (26 नवंबर, 2023) के अवसर पर "ए गाइड टू अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन" नामक एक हैंडबुक जारी की गई।
विदेशी कानून फर्म	बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि विदेशी वकीलों/ कानून फर्मों का भारत में प्रवेश पारस्परिक आधार पर होगा।
भारतीय विधि आयोग	22वें विधि आयोग द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट: 279वीं रिपोर्ट - राजद्रोह के कानून की आवश्यकता। 280वीं रिपोर्ट - प्रतिकूल कब्जे (Adverse Possession) पर कानून। 282वीं रिपोर्ट - ऑनलाइन FIR दर्ज करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) में संशोधन। 283वीं रिपोर्ट - POCSO अधिनियम, 2012 के तहत सहमति की आयु।

3. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronics & Information Technology)

सेमीकॉन इंडिया 2023, गांधीनगर (गुजरात)	इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ने गुजरात में 'सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन, 2023' का आयोजन किया। इसकी थीम थी, 'कैटालाइजिंग इंडियाज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम'।
ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (GPAI)	नई दिल्ली में आयोजित GPAI सम्मेलन में नई दिल्ली घोषणा-पत्र (New Delhi Declaration) को अपनाया गया। इसमें सुरक्षित, विश्वसनीय और भरोसेमंद AI के विकास तथा GPAI परियोजनाओं की सततता का समर्थन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है।
इंडिया स्टैक	- RuPay डेबिट कार्ड और BHIM-UPI से कम राशि के लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। - UIDAI ने आधार आधारित फिंगरप्रिंट सत्यापन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / मशीन लर्निंग पर आधारित एक नया सुरक्षा तंत्र शुरू किया। - आधार से संबंधित डेटा को ऑनलाइन निःशुल्क अपडेट की सुविधा दी गई है।

⁷ Arbitration Council of India

⁸ New Delhi International Arbitration Centre

⁹ India International Arbitration Centre

¹⁰ Alternative Dispute Resolution

G20 पहल	- पहली G-20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप (DEWG) की बैठक लखनऊ में आयोजित हुई। - डिजिटल इनोवेशन एलायंस (DIA) प्रोग्राम की बैठक बेंगलुरु में आयोजित हुई।
अन्य सरकारी पहलें	- भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को 15वें वित्त आयोग की अवधि (2021-22 से 2025-26) के दौरान जारी रखने को मंजूरी दी। - आई.टी. हार्डवेयर के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन योजना- 2.0 शुरू की गई। - डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्रों में सहयोग हेतु भारत और सऊदी अरब के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन (MoC) को मंजूरी दी गई है।

4. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (Ministry of Environment, Forest and Climate Change)

जलवायु परिवर्तन	- जलवायु परिवर्तन पर COP28 सम्मेलन के दौरान ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम (GCP) लॉन्च किया गया। - ग्रीन क्रेडिट नियमावली, 2023 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया गया। - राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC)¹¹ में तय लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में भारत की उपलब्धियां: 31 अक्टूबर, 2023 तक, गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से कुल संचयी विद्युत की स्थापित क्षमता 186.46 मेगावाट थी। यह कुल संचयी विद्युत स्थापित क्षमता का 43.81 प्रतिशत है। 2005 से 2019 के बीच देश में GDP की तुलना में उत्सर्जन तीव्रता (Emission intensity) में 33 प्रतिशत की कमी कर ली गई है। - भारत ने UNFCCC के समक्ष तीसरी नेशनल कम्युनिकेशन रिपोर्ट प्रस्तुत की: इसके मुताबिक मानवजनित गतिविधियों से उत्सर्जन में सर्वाधिक 75.81% हिस्सेदारी ऊर्जा क्षेत्र की है। इसके बाद कृषि क्षेत्र (13.44 प्रतिशत), औद्योगिक प्रक्रिया और उत्पाद उपयोग/IPPU (8.41 प्रतिशत) तथा अपशिष्ट (2.34 प्रतिशत) की हिस्सेदारी है। - इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान: 1 जनवरी, 2020 तक बेसलाइन की तुलना में हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन (HCFC) के उपयोग में 35% की कमी का लक्ष्य रखा गया था। भारत ने इस लक्ष्य से आगे जाकर 44% की कमी हासिल कर ली। - HCFC फेज आउट मैनेजमेंट प्लान (HPMP) चरण-II के कार्यान्वयन के दौरान, भारत ने कठोर फोम के निर्माण में HCFC- 141b के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाला भारत पहला विकासशील देश है।
भारत की अध्यक्षता में G-20 की पहलें	- गांधीनगर कार्यान्वयन रोडमैप और गांधीनगर सूचना मंच (GIR-GIP): यह वनाग्नि और खनन प्रभावित क्षेत्रों में भूमि पुनर्बहाली पर एक वैश्विक गठबंधन है। - रिसोर्स एफिशिएंसी सर्कुलर इकोनॉमी इंडस्ट्री कोएलिशन (RECEIC) की शुरुआत की गई। - हाई-लेवल प्रिंसिपल्स फॉर ए सस्टेनेबल एंड रेसिलिएंट ब्लू/ ओसियन बेस्ड इकोनॉमी (HLPsRBE) जारी की गई।
वन संरक्षण	- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) ने 1 सितंबर, 2023 को भारत में स्थित सभी 75 रामसर साइट्स (वेटलैंड्स) में पाए जाने वाले जीव-जंतुओं की सूची प्रकाशित की। - भारत की सभी 75 रामसर साइट्स में पाई जाने वाली वनस्पतियों की सूची तैयार की जा रही है। - वन (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2023 लागू किया गया। - विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून, 2023) के अवसर पर मैंग्रोव के लिए मिष्टी (MISHTI) पहल शुरू की गई।

¹¹ Nationally determined contribution

	○ MISHTI से आशय है- तटरेखा पर्यावासों और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल (MISHTI)¹²। ● ब्लू फ्लैग समुद्र तट: 2022 में, भारत के कुल 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ।
परिवेश (PARIVESH)	● गतिशक्ति पोर्टल (GatiShakti Portal) के साथ परिवेश 2.0 का एकीकरण किया गया। ○ परिवेश एक वेब आधारित और भूमिका आधारित वर्कफ्लो एप्लिकेशन है। इस एप्लिकेशन का उपयोग करके परियोजनाओं के लिए विभिन्न प्राधिकरणों से पर्यावरण, वन, वन्यजीव और तटीय विनियमन ज़ोन (CRZ)¹³ संबंधी मंजूरी प्राप्त करने हेतु आवेदन किए जा सकते हैं और आवेदन पर आगे की कार्रवाई पर नजर रखी जा सकती है।
वायु गुणवत्ता/प्रदूषण	● आधार वर्ष (Base year) 2017 की तुलना में 2022-23 में 90 शहरों में वार्षिक PM10 स्तर में गिरावट आई है, यानी वायु गुणवत्ता स्तर में सुधार हुआ है।
सर्कुलर इकोनॉमी	● सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कानूनों में संशोधन किए गए: ○ प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ○ खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार आवाजाही) नियम, 2016 में यूज्ड ऑयल के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (EPR)¹⁴ प्रावधान जोड़ने के लिए अधिसूचना जारी, ○ ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, ○ बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम।
वन्यजीव	● चीते को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में भेजना: सितंबर 2022 में नामीबिया से 8 चीतों एवं फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया। ● प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष: भारत में दुनिया के 75% से अधिक बाघ पाए जाते हैं। (बाघ गणना, 2023) ● वनस्पतियों, जीवों और हर्बेरियम की सूची का डिजिटलीकरण: भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (BSI) और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) ने 16500 प्रजाति के नमूनों का डिजिटलीकरण किया है, साथ ही टाइप और नॉन-टाइप प्रकार के भारतीय जीव-जंतुओं की 45000 इमेज भी डाली गई है।

5. उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय) {Department For Promotion of Industry and Internal Trade (Ministry of Commerce & Industry)}

G-20 पहल	● स्टार्ट-अप 20 एंगेजमेंट ग्रुप को संस्था का रूप दिया गया। यह G-20 सदस्यों के स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े हितधारकों के लिए संवाद फोरम है।
उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) ¹⁵ योजना	● देश के 24 राज्यों के 150 से अधिक जिलों में PLI यूनिट्स स्थापित की गई हैं। ● 3 वर्षों की अवधि के भीतर मोबाइल विनिर्माण में घरेलू वैल्यू एडिशन (स्थानीय उपकरण) 20% का हो गया है। ● दूरसंचार क्षेत्र में उपयोगी उपकरणों के आयात को कम करने के 60% लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है। अब भारत एंटीना, GPON (गीगाबिट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क) और CPE (कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट) उपकरणों के मामले में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है।

¹² Mangrove Initiative for Shoreline Habitats & Tangible Incomes

¹³ Coastal Regulation Zone

¹⁴ Extended Producer Responsibility

¹⁵ Production Linked Incentive

	- CT स्कैन, MRI जैसे चिकित्सा उपकरणों के निर्माण में दूसरे देशों से भारत में प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण हुआ है। - ड्रोन क्षेत्रक के कारोबार में 7 गुना उछाल देखा गया है। इसमें सभी MSME स्टार्टअप शामिल हैं।
स्टार्ट-अप इंडिया पहल	1.14 लाख से अधिक स्टार्टअप्स को मान्यता दी गई है। इन स्टार्टअप्स ने 12 लाख से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। - DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त 21,800 से अधिक स्टार्टअप्स गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) से जुड़ चुके हैं। - स्टार्टअप इंडिया ने राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों के क्षमता निर्माण और अनुभव प्राप्ति हेतु 3 क्षेत्रीय और 2 अंतर्राष्ट्रीय विजिट का आयोजन किया।
ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC)	- ONDC प्लेटफॉर्म से नवंबर 2023 में 600 से अधिक शहरों में 6.3 मिलियन से अधिक लेनदेन किए गए। - लगभग 400 स्वयं सहायता समूहों, सूक्ष्म उद्यम से जुड़े उद्यमियों (micro-entrepreneurs) और सामाजिक क्षेत्रक के उद्यमियों को इसमें शामिल किया गया है। - ONDC प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेंगलुरु, मैसूर, कोच्चि और कोलकाता में मोबिलिटी सेवा (कैब राइड्स इत्यादि) चालू है। - ONDC टीम ने निर्यात के लिए एक पायलट परियोजना का सफलतापूर्वक संचालन किया है। इसके तहत सिंगापुर, ONDC नेटवर्क के माध्यम से भारतीय विक्रेताओं से उत्पाद खरीदने वाला पहला मार्केट है।
एक जिला एक उत्पाद (ODOP)	- राज्यों में ODOP-एकता/यूनिटी मॉल की स्थापना की जा रही है। - यूनिटी मॉल की स्थापना के लिए 27 में से 17 राज्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई है।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB)	- अलग-अलग मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा नियमों के पालन से जुड़े 3,600 से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटा दिया गया है और 41,000 से अधिक अनुपालनों को कम कर दिया गया है। - संसद ने जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक, 2023 पारित कर दिया। - राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (National Single Window System) से वर्तमान में 32 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और 25 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़े अलग-अलग प्रकार की मंजूरी दी जा रही है।
पी.एम. गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान (NMP)	- अवसंरचना, सामाजिक एवं आर्थिक के क्षेत्र में कार्यरत 39 केंद्रीय मंत्रालयों के अलग-अलग पोर्टल विकसित कर उन्हें NMP के साथ एकीकृत किया गया है। स्टेट मास्टर प्लान (SMP) पोर्टल्स: अवसंरचना परिसंपत्तियों को चिह्नित कर उनमें समन्वय स्थापित करने के लिए 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों हेतु SMP पोर्टल्स विकसित किए गए हैं।
लॉजिस्टिक्स	लॉजिस्टिक्स इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) 2023 रिपोर्ट का 5वां संस्करण जारी किया गया। 23 राज्यों ने अपनी-अपनी राज्य लॉजिस्टिक्स नीतियों को अधिसूचित कर दिया है। - आठ अलग-अलग मंत्रालयों की 35 प्रणालियों को यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) से जोड़ दिया गया है।
औद्योगिक क्षेत्रक का प्रदर्शन	- वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)¹⁶ ने 6.9% (पिछले वर्ष की तुलना में) की संचयी वृद्धि दर्ज की। - वित्त वर्ष 2023-24 की अप्रैल-अक्टूबर अवधि के दौरान, कोर उद्योगों का उत्पादन 8.6% (पिछले वर्ष की तुलना में) बढ़ गया।

¹⁶ Index of Industrial Production

बौद्धिक संपदा	- ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (GII) 2023 में भारत 40वें स्थान पर था। 2022 के इंडेक्स में भी भारत 40वें स्थान पर ही था। 2014-15 और 2023-24 के बीच महिलाओं द्वारा दायर पेटेंट की संख्या में 345 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।
---------------	--

6. वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Commerce)

विदेश व्यापार नीति, 2023	- विदेश व्यापार नीति 2023 (FTP 2023) नीति जारी की गई। यह निम्नलिखित 4 पिलर्स पर आधारित है: - आर्थिक प्रोत्साहन की जगह कर छूट देने पर फोकस, - सहभागिता के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना, - कारोबार करना आसान बनाना, - उभरते क्षेत्रक- ई-कॉमर्स जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करना और 'स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गनिज्म्स, मैटेरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज' (स्कोमेट/SCOMET) नीति को सुव्यवस्थित करना। - विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत की जा रही पहलें - एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, - निर्यातकों के लिए वन-टाइम माफी योजना, "निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर" योजना के माध्यम से नए कस्बों की पहचान तथा "स्टेटस होल्डर स्कीम" के माध्यम से निर्यातकों की पहचान करना।
भारत की अध्यक्षता में G-20 की पहलें	- व्यापार और निवेश पर G-20 मंत्रिस्तरीय बैठक, जयपुर; "व्यापार डाक्यूमेंट्स के डिजिटलीकरण पर उच्च-स्तरीय सिद्धांतों" को अपनाया गया; - MSMEs के लिए सूचना तक पहुंच बढ़ाने के लिए "जयपुर कॉल फॉर एक्शन" जारी; - G-20 जेनेरिक मैपिंग फ्रेमवर्क: यह ग्लोबल वैल्यू चैन के मुख्य डेटा, विश्लेषण और प्रतिनिधित्व के प्रमुख आधार (बिल्डिंग ब्लॉक) के लिए फ्रेमवर्क है।
भारत मंडपम	यह नई दिल्ली में स्थित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह कन्वेंशन सेंटर (IECC)¹⁷ परिसर है। इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक व्यवसाय केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
द्विपक्षीय सहयोग	भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका - दोनों देशों ने व्यापार संबंध को मजबूत करने और विस्तार देने के लिए 'रेसिलिएंट ट्रेड' पर नए व्यापार नीति फोरम कार्य समूह का गठन किया। - सेमीकंडक्टर सप्लाई चैन और नवाचार साझेदारी पर एक समझौता जापान पर हस्ताक्षर किए गए। "इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाना" पर एक समझौता जापान पर हस्ताक्षर किए गए। "इनोवेशन हैंडशेक" की स्थापना की गई।

¹⁷ International Exhibition-cum-Convention Centre

	भारत - संयुक्त अरब अमीरात - भारत - संयुक्त अरब अमीरात CEPA की संयुक्त समिति (JC) की पहली बैठक आयोजित की गई। - CEPA की प्रभावी निगरानी के लिए तरजीही व्यापार डेटा के पारस्परिक आदान-प्रदान पर सहमति बनी। - MSMEs और स्टार्ट-अप पर ध्यान देने के साथ B2B भागीदारी तंत्र के रूप में UAE - भारत CEPA परिषद (UICC)¹⁸ की स्थापना पर सहमति व्यक्त की गई।
इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी (IPEF) मंत्रिस्तरीय बैठक	IPEF सप्लाई चेन को अधिक लचीला, मजबूत और अच्छी तरह से एकीकृत बनाने के लिए IPEF सप्लाई चेन रेसिलिएंस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
आयात/ निर्यात से संबंधित नीतियां	- विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के तहत निर्यात दायित्वों का विस्तार करने हेतु कंपोजिशन शुल्क की गणना को सरल बनाने के लिए संशोधित नियमों को अधिसूचित किया। - निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों में छूट (Remission of Duties and Taxes on Exported Products: RoDTEP) योजना के तहत दी जानी वाली सहायता को 30 जून, 2024 तक बढ़ा दिया गया।
अन्य पहलें	- APEDA ने ग्लोबल मिलेट्स (श्री अन्न) सम्मेलन का आयोजन किया। - राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड (National Turmeric Board) की स्थापना की गई।

7. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution)

मूल्य निगरानी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में प्रयास	- प्राइस मॉनिटर सेल से 22 आवश्यक वस्तुओं के थोक और खुदरा मूल्यों पर नजर रखी जाती है। - मूल्य रिपोर्टिंग केंद्रों की संख्या बढ़कर 550 हो गई है (2023 में 140 रिपोर्टिंग केंद्र जोड़े गए)। - प्राइस मॉनिटर सेल को मजबूत करने के लिए योजना के परिचालन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। - दैनिक आधार पर मूल्य की रिपोर्टिंग के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। - पूर्वानुमानित मूल्य पूर्वानुमान मॉडल (PPFR)¹⁹ लॉन्च किया गया।
मूल्य में उतार-चढ़ाव की निगरानी के लिए "मूल्य स्थिरीकरण कोष"	इसकी स्थापना 2014-15 में बागवानी उत्पादों (कमोडिटी) के मूल्य में अधिक उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए की गई थी।
भारत दाल (Bharat Dal) ब्रांड	- उपभोक्ताओं को वहनीय कीमत पर चना दाल उपलब्ध कराने के लिए भारत दाल ब्रांड शुरू किया गया है। - इसके अलावा सब्सिडी कीमत पर आटा उपलब्ध कराने के लिए भारत आटा ब्रांड भी लॉन्च किया गया।

¹⁸ UAE-India CEPA Council

¹⁹ Predictive price forecasting model

विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (15 मार्च, 2023)	इस आयोजन की थीम थी; "क्लीन एनर्जी ट्रांजीशन के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना"।
डार्क पैटर्न की रोकथाम और विनियमन के लिए दिशा-निर्देश, 2023	"भ्रामक विज्ञापनों" या "अनुचित व्यापार व्यवहार" की प्रकृति के समान डार्क पैटर्न को विनियमित करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत दिशा-निर्देश जारी किए गए। - इन दिशा-निर्देशों में 13 प्रकार के डार्क पैटर्न का उल्लेख है। इनमें फॉल्स अर्जेन्सी, बास्केट स्लीकिंग, कन्फर्म शेमिंग, सब्सक्रिप्शन ट्रेप, दुर्भावनापूर्ण मैलवेयर आदि शामिल हैं।
उपभोक्ता संबंधी शिकायतें दर्ज करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल	उपभोक्ता शिकायत/ अपील को ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए "edaakhil.nic.in" नामक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल विकसित किया गया है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में सुधार	उपभोक्ता देशभर से 17 भाषाओं में टोल-फ्री नंबर 1915 के जरिए अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं।
कॉन्फोनेट/ CONFONET एप्लिकेशन	2007 में लॉन्च किए गए कॉन्फोनेट को प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और उपयोग को अपग्रेड करके आधुनिक बनाया गया है। - यह CMS²⁰, OCMS²¹, ई-दाखिल और NCDRC²² मॉड्यूल को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करता है। - उपभोक्ता द्वारा दायर केस की प्रबंधन प्रक्रिया में सुधार के लिए ई-जागृति नामक एक अपग्रेडेड नया केंद्रीय सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन लॉन्च किया गया।
मानकों का विकास	- अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान, 1320 मानक तैयार किए गए और 2118 मानकों की समीक्षा की गई। 8500 भारतीय मानकों को ISO/ IEC मानकों के अनुरूप बनाया गया है। - भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने मानक निर्धारण पर राष्ट्रीय कार्य योजना (SNAP) (2022-27) जारी की।
हॉलमार्किंग की दिशा में प्रयास	- अप्रैल-नवंबर 2023 के बीच BIS द्वारा मान्यता प्राप्त परख और हॉलमार्किंग केंद्रों की संख्या 1403 से बढ़कर 1499 हो गई। - सोने के आभूषणों/ कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में संशोधन किया गया। 'ज़ीरो डिफेक्ट, ज़ीरो इफेक्ट' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समावेशी मानकीकरण और अच्छे विनियामक उदाहरणों के माध्यम से सततता का पता लगाने के लिए BIS द्वारा "G-20 मानक संवाद, 2023" आयोजित किया गया।

²⁰ Case Monitoring System

²¹ Online Case Monitoring System

²² National Consumer Disputes Redressal Commission

लीगल मेट्रोलाजी की दिशा में किए गए प्रयास	- लीगल मेट्रोलाजी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया। - लीगल मेट्रोलाजी (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2011 में संशोधन किया गया। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद से जुड़े उद्योगों को डिजिटल रूप में कुछ अनिवार्य घोषणाएं जारी करने की अनुमति देना है।
अंतर्राष्ट्रीय लीगल मेट्रोलाजी संगठन (The International Organization of Legal Metrology: OIML)	- भारत को OIML अनुमोदन प्रमाण-पत्र (Approval certificate) जारी करने का अधिकार दिया गया है। ऐसा अधिकार प्राप्त करने वाला भारत दुनिया का 13वां देश है। - वजन और माप उपकरणों के घरेलू निर्माता अतिरिक्त परीक्षण शुल्क चुकाए बिना दुनिया भर में वजन और माप उपकरणों का निर्यात कर सकते हैं। - OIML अनुमोदन प्रमाण-पत्र जारी करने से जुड़े शुल्क लगाकर भारत विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकता है। - OIML एक अंतर-सरकारी संगठन है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वजन या मापन उपकरणों को बेचने के लिए अनुमोदन प्रमाण-पत्र प्रदान करता है।
उपभोक्ता जागरूकता की दिशा में किए गए प्रयास	- उपभोक्ता संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए नया शुभंकर (Mascot) "जागृति" लॉन्च किया गया। - उपभोक्ताओं के बीच जागरूकता फैलाने के लिए देश भर के टियर-2 और टियर-3 शहरों के सिनेमा थिएटरों का उपयोग किया जा रहा है।

8. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय (Ministry of Labour and Employment)

राष्ट्रीय करियर सेवा (National Career Service: NCS) परियोजना	- NCS पोर्टल को एक व्यापक अखिल भारतीय नेटवर्क के रूप में विकसित करने के लिए 28 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्रों के साथ जोड़ा गया है। - इसे 2015 में शुरू किया गया था। उस समय से लेकर 30 नवंबर, 2023 तक NCS प्लेटफॉर्म पर रोजगार चाहने वाले 3.64 करोड़ से अधिक उम्मीदवार पंजीकृत थे, और 19.15 लाख नियोक्ता और 1.92 करोड़ से अधिक रिक्तियां सूचीबद्ध हैं।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (ABRY)	- इसे कोविड-19 महामारी के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव को कम करने और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 2020 में शुरू किया गया था। 05 दिसंबर, 2023 तक 60.48 लाख लाभार्थियों को 10,043.02 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (Employees State Insurance Corporation: ESIC)	- इसका विस्तार लक्षद्वीप सहित देश के 611 जिलों में कर दिया गया है। इसके नेटवर्क में 161 अस्पताल और 1,574 औषधालय शामिल हैं। - इसके तहत बीमित व्यक्तियों (Insured Persons: IPs) की संख्या बढ़कर 3.72 करोड़ से अधिक हो गई है। यह 12 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान कर रहा है। - ESIC ने अपने 38 अस्पतालों में कीमोथेरेपी सेवाएं शुरू की हैं। 5G एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation: EPFO)	किए गए सुधार: पारदर्शी कंप्यूटर-जनित निरीक्षण प्रणाली, ई-पासबुक की शुरुआत, उमंग/ UMANG पोर्टल के साथ जुड़ना, प्रशासनिक शुल्क में कमी, सरलीकृत मासिक इलेक्ट्रॉनिक चालान सह-रिटर्न आदि।

G-20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक	- वैश्विक स्तर पर कौशल संबंधी कमियों को दूर करने की रणनीतियों पर G-20 नीति की प्राथमिकताएं। - गिग और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए पर्याप्त एवं संधारणीय सामाजिक सुरक्षा तथा कार्य की बेहतर दशाओं पर G-20 नीतिगत प्राथमिकताएं। - सामाजिक सुरक्षा के संधारणीय वित्त-पोषण के लिए G-20 नीतिगत विकल्प।
---------------------------------------	---

9. भूमि संसाधन विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) {Department of Land Resources (Ministry of Rural Development)}

डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (Digital India Land Records Modernization Programme: DILRMP)	- यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। इसका उद्देश्य भूमि से संबंधित रियल-टाइम जानकारी में सुधार करना है। - बदलाव और उपलब्धियां: - DILRMP की अवधि पांच साल (2021-22 से 2025-26) के लिए बढ़ा दी गई है। 95.08 प्रतिशत रिकॉर्ड ऑफ राइट्स (RoR) पूरा हो चुका है। - DILRMP के तहत अन्य पहलें: - विशिष्ट भूमि खंड पहचान संख्या (ULPIN)²³ या भू-आधार: इसे 29 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने अपनाया है। - राष्ट्रीय जेनेरिक दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (NGDRS)²⁴ या ई-पंजीकरण: 18 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने एक राष्ट्र एक पंजीकरण सॉफ्टवेयर को अपनाया है। - भूमि-रिकॉर्ड/ डेटाबेस पंजीकरण के साथ ई-कोर्ट का जुड़ाव: 26 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को संबंधित उच्च न्यायालयों से मंजूरी प्राप्त है। - सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं में भूमि अभिलेखों का लिप्यंतरण (Transliteration): 17 राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश भूमि रिकॉर्ड में लिप्यंतरण उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। - भूमि सम्मान: 168 जिलों ने 99 प्रतिशत या उससे अधिक कार्य पूरा करके प्लेटिनम ग्रेडिंग सर्टिफिकेट हासिल किया है।
---	--

10. पशुपालन एवं डेयरी विभाग (मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय) {Department of Animal Husbandry & Dairying (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying)}

पशुधन क्षेत्रक	- इस क्षेत्रक की 2021-22 में कुल GVA (सकल मूल्य वर्धित) में हिस्सेदारी 5.73% थी। - वर्ष 2014-15 से 2021-22 तक इस क्षेत्रक ने 13.36% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से संवृद्धि हासिल की है।
डेयरी क्षेत्रक	- डेयरी या दुग्ध भारत में कृषि से संबंधित एकल सबसे बड़ी कृषि उत्पाद है। इसका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान है। यह क्षेत्रक 8 करोड़ से अधिक किसानों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करता है। - भारत विश्व में दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर दुग्ध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 24.64 प्रतिशत है।

²³ Unique Land Parcel Identification Number

²⁴ National Generic Document Registration System

	- पिछले 9 वर्षों में दुग्ध उत्पादन में 5.85 प्रतिशत CAGR की दर से बढ़ोतरी हुई है। 2022-23 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 459 ग्राम प्रति दिन थी, जबकि 2022 में वैश्विक औसत 322 ग्राम था।
अंडा एवं मांस उत्पादन	- खाद्य और कृषि संगठन कॉर्पोरेट सांख्यिकीय डेटाबेस (FAOSTAT) उत्पादन डेटा (2021) के अनुसार, भारत दुनिया में अंडा उत्पादन में दूसरे और मांस उत्पादन में 5वें स्थान पर है। - देश में अंडों का उत्पादन पिछले 9 वर्षों में 7.35% की CAGR दर से बढ़ रहा है।

11. मत्स्य पालन विभाग (मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय) {Department of Fisheries (Ministry of Fisheries, Animal Husbandry & Dairying)}

मत्स्य पालन क्षेत्रक	- भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 8 प्रतिशत है। - यह देश के सकल मूल्य वर्धित (GVA) में लगभग 1.09% और कृषि GVA में 6.724% से अधिक का योगदान देता है।
G-20 कृषि मंत्रियों की बैठक	G-20 कृषि मंत्रियों की बैठक का विषय जैव विविधता के संबंध में 'पौष्टिक भोजन के लिए सतत कृषि', 'खेती विस्तार और कृषि में महिलाओं की भूमिका' था।
प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) 2020-21 से अब तक	- अंतर्देशीय मत्स्य पालन: 44,408 पिंजरों, अंतर्देशीय जलीय कृषि के लिए 20,849.41 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र, 788 मछली और 4 स्कैपी हैचरीज आदि को मंजूरी दी गई है। - समुद्री मत्स्य पालन: मशीनीकृत मत्स्यन जहाजों में 2,255 जैव-शौचालयों, मछली पालन के लिए 1,518 खुले समुद्र पिंजरे, लवणीय जल में की जाने वाली जलीय कृषि के लिए 1,380.86 हेक्टेयर तालाब क्षेत्र, 463 गहरे समुद्र वाले मत्स्यन जहाजों आदि को मंजूरी दी गई है। - मछुआरा कल्याण: मछुआरों को पुरानी नौकाओं के बदले 6,498 नई नौकाएं और नेट प्रदान की गई, 5,97,709 मछुआरों के परिवारों के लिए आजीविका एवं पोषण संबंधी सहायता को मंजूरी दी गई है आदि। - मत्स्य पालन अवसंरचना: मोटर साइकिल, आइस बॉक्स वाली साइकिल, ऑटो रिक्शा, इंसुलेटेड ट्रक जैसी मत्स्य परिवहन सुविधाओं की 26,067 इकाइयों को मंजूरी दी गई है। - जल क्षेत्रक में स्वास्थ्य प्रबंधन: 17 रोग निदान केंद्र और गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाएं, 29 मोबाइल केंद्र एवं परीक्षण प्रयोगशालाएं तथा 5 जलीय रेफरल प्रयोगशालाएं स्वीकृत की गई हैं। - सजावटी मत्स्य पालन: 2,153 सजावटी मत्स्य पालन इकाइयां और 163 एकीकृत सजावटी मत्स्य इकाइयों (प्रजनन व पालन) को मंजूरी दी गई है। - समुद्री सिवार (Seaweed) की खेती: 46,095 राफ्ट और 66,330 मोनोलाइन ट्यूब नेट स्वीकृत किए गए हैं। - पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास: नए तालाबों के निर्माण, एकीकृत मत्स्य पालन आदि के लिए 1,391.62 करोड़ रुपये की कुल परियोजना लागत को मंजूरी दी गई है।
प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना (PM-MKSSY)	- यह PMMSY के तहत एक केंद्रीय क्षेत्रक की उप-योजना है। इसकी शुरुआत मछुआरों, मछली विक्रेताओं तथा सूक्ष्म और लघु उद्यमों की गतिविधियों को बढ़ाने व अधिक सक्षम बनाने के लिए की गई थी। - PM-MKSSY में डिजिटल समावेशन सहित असंगठित मत्स्य पालन क्षेत्रक को चरणबद्ध तरीके से संगठित बनाने पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है।

अन्य पहलें	- जलीय पशु रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम के तहत मोबाइल ऐप "रिपोर्ट फिश डिजीज" लॉन्च किया गया है। - वैश्विक मत्स्य पालन सम्मेलन भारत, 2023 का आयोजन गुजरात साइंस सिटी, अहमदाबाद में किया गया था।
------------	---

12. वस्त्र मंत्रालय (Ministry of Textile)

पीएम मित्र (पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल: PM MITRA)	- प्लग एंड प्ले सुविधाओं (न्यूनतम प्रक्रियाओं से युक्त) के साथ विश्व स्तरीय अवसंरचना विकसित करने के लिए पीएम मित्र पार्क योजना की शुरुआत की गई है। - यह 5F विज़न- 'फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरिन' से प्रेरित है। - वस्त्र क्षेत्रक हेतु पांच साल की अवधि के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना को मंजूरी दी गई है।
कस्तूरी कॉटन भारत	- यह भारत सरकार, व्यापार निकायों और उद्योगों की एक संयुक्त पहल है। इसके तहत भारतीय कपास को बढ़ावा देने के लिए ब्रांडिंग, ट्रेसेबिलिटी और प्रमाणन का कार्य किया जाता है। - भारतीय कपास निगम (CCI)²⁵, वस्त्र मंत्रालय और TEXPROCIL (टेक्सप्रोसिल) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस MoU का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्रक में स्व-विनियमन को प्रोत्साहित करना है।
राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (National Technical Textile Mission: NTTM)	- इसके मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं: - अनुसंधान नवाचार एवं विकास; - संवर्धन एवं बाजार विकास; - शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास; - निर्यात प्रोत्साहन आदि।
संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (Amended Technology Upgradation Fund Scheme: ATUFS)	AUTFS के तहत, MSME और गैर-MSME का अनुपात 89:11 है, जबकि TUFS के पिछले संस्करणों के तहत यह अनुपात 30:70 था।
समर्थ/ SAMARTH	इसका उद्देश्य मांग आधारित और प्लेसमेंट उन्मुख राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF)²⁶ के अनुरूप कौशल कार्यक्रम प्रदान करना है।
कपास क्षेत्रक	CCI ने कपास के प्रोसेसिंग और भंडारण से लेकर इसकी ई-नीलामी बिक्री तक ब्लॉक चेन तकनीक का उपयोग करके QR कोड लागू किया है।
जूट क्षेत्रक	- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जूट वर्ष 2023-24 के लिए अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों को मंजूरी प्रदान कर दी है:- - खाद्यान्नों की शत-प्रतिशत पैकिंग जूट के बोरो में की जाएगी और - चीनी की 20% पैकिंग अनिवार्य रूप से जूट के बोरो में की जाएगी। - जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 में जूट किसानों, श्रमिकों और जूट के सामान के उत्पादन में लगे व्यक्तियों के हितों की रक्षा का प्रावधान किया गया है।

²⁵ Cotton Corporation of India

²⁶ National Skill Qualification Framework

रेशम क्षेत्रक	- अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड गुणवत्ता वाले रेशम का उत्पादन वर्ष 2013-14 में 25% से बढ़कर 2022-23 में 35% हो गया था। - प्रति हेक्टेयर कच्चे रेशम की पैदावार 2013-14 के दौरान 95.93 किलोग्राम की तुलना में 2022-23 के दौरान बढ़कर 109.23 किलोग्राम हो गई थी।
ऊन क्षेत्रक	एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम (IWDP)²⁷ 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान लागू की जाने वाली एक केंद्रीय क्षेत्रक की योजना है।
हथकरघा क्षेत्रक	लाभार्थियों को मुद्रा/ MUDRA योजना के तहत सहायता प्रदान की जा रही है।
इंडिया टेक्स 2024	वस्त्र मंत्रालय के समर्थन से 11 कपड़ा निर्यात संवर्धन परिषदों के एक संघ ने 'ग्लोबल टेक्सटाइल मेगा इवेंट' आयोजित किया है।

13. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation)

बहुपक्षीय एजेंसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और भागीदारी	- भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (UNSC) के सदस्य के रूप में चुना गया है। सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल चार वर्षों का होगा, जो 01 जनवरी, 2024 से शुरू होगा। - भारत निम्नलिखित के लिए फिर से निर्वाचित हुआ है- - सांख्यिकी पर UN ESCAP समिति (CST) के ब्यूरो के तीन उपाध्यक्षों में से एक के रूप में, और 2022-2024 की अवधि हेतु एशिया और प्रशांत के लिए सांख्यिकीय संस्थान (SIAP)²⁸ की गवर्निंग काउंसिल के लिए।
MPLADS पर संशोधित दिशा-निर्देश और नए वेब-पोर्टल का शुभारंभ	- नए वेब पोर्टल में MPLADS विकास परियोजनाओं के लिए कई प्रौद्योगिकी-सक्षम कार्य तथा ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शामिल हैं। - इन प्रौद्योगिकी-सक्षम कार्यों में शामिल हैं- नए वेब-पोर्टल में MPLADS विकास परियोजना के संपूर्ण जीवन चक्र और ऑनलाइन कार्य अनुशंसा, ऑनलाइन मंजूरी/ अस्वीकृति, डैशबोर्ड, चेतावनी जारी करने, उपयोग/ पूर्णता प्रमाण-पत्र को स्वचालित तरीके से जारी करने, वेंडरों को भुगतान जैसी ऑनलाइन निगरानी प्रणाली से लैस कई प्रौद्योगिकी-समर्थ विशेषताएं आदि। - MPLADS- संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना²⁹।
डेटा विजुअलाइज़ेशन	पहली बार डेटा विजुअलाइज़ेशन सेक्शन को MoSPI की वेबसाइट पर जोड़ा गया है।

14. भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries)

भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण योजना, चरण-II	- इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं को 5,228 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है। 148 EV सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन (PCS) चालू किए गए हैं।
--	---

²⁷ Integrated Wool Development Programme

²⁸ Statistical Institute for Asia and the Pacific

²⁹ Members of Parliament Local Area Development Scheme

फेम/ FAME इंडिया चरण-II)	7432 सार्वजनिक फास्ट चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए 800 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है।
ऑटोमोबाइल और ऑटो कॉम्पोनेन्ट के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन (PLI) योजना	5 वर्षों की अवधि के लिए 25,938 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एक PLI योजना को मंजूरी दी गई है। - इसमें 'एडवांस्ड ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी' (AAT) उत्पादों के घरेलू विनिर्माण और ऑटोमोटिव विनिर्माण मूल्य श्रृंखला में निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन का प्रस्ताव दिया गया है।
एडवांस केमिस्ट्री सेल (ACC) के लिए विनिर्माण सुविधाओं हेतु PLI योजना	इसे भारत की एडवांस केमिस्ट्री सेल (ACC) संबंधी विनिर्माण क्षमताओं और ACC निर्यात को बढ़ाने हेतु शुरू किया गया है।
GST रियायत प्रमाण-पत्र	- नवंबर, 2020 में आधार प्रमाणित GST रियायत प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया था। - इस पोर्टल के माध्यम से वर्तमान और पिछले वर्ष में कुल 5513 GST रियायत प्रमाण-पत्र जारी किए गए हैं।
अन्य प्रमुख पहलें	- टुवाइर्स पंचामृत: यह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यक्रम है। - जुलाई 2023 में बेंगलुरु में 'रोबोटिक्स पर राष्ट्रीय सम्मेलन' आयोजित किया गया था। - भारत का चयनात्मक उत्प्रेरक रिएक्टर्स (SCRs)³⁰ का पहला सेट BHEL ने निर्मित किया है। इसे तेलंगाना में यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन के लिए निर्मित किया गया है। चयनात्मक उत्प्रेरक रिएक्टर्स को नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) उत्सर्जन को सीमित करने के लिए निर्मित किया है। - भेल (BHEL) संवाद 3.0- आयातित वस्तुओं के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने से संबंधित है।

15. पर्यटन मंत्रालय (Ministry of Tourism)

भारत की अध्यक्षता में G-20 पहलें	5 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के साथ पर्यटन के लिए G-20 रोडमैप: सतत विकास लक्ष्य (SDGs) प्राप्त करने के लिए हरित पर्यटन, डिजिटलीकरण, कौशल, पर्यटन MSMEs और गंतव्य प्रबंधन। - G-20 रोडमैप के तहत 'ट्रैवल फॉर लाइफ (LiFE)' पहल- इसे विश्व पर्यटन दिवस (27 सितंबर, 2023) पर औपचारिक रूप से शुरू किया गया था। - जयपुर में G-20 टूरिज्म एक्सपो का आयोजन किया गया था।
भारत भ्रमण वर्ष 2023	2023 को भारत भ्रमण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। - भारत टोक्यो में आयोजित जाटा (JATA) ट्रैवल एक्सपो का भागीदार देश था।
भारत में पर्यटन को बढ़ावा देना	- पूर्वोत्तर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया था। - यह अभूतपूर्व पहल वैश्विक मंच पर एक प्रमुख विवाह स्थल के रूप में भारत की सुंदरता और विविधता को प्रदर्शित करती है।

³⁰ Selective Catalyst Reactors

	कृष्णवेणी संगीत नीरजनम, अपनी तरह का एक संगीत और सांस्कृतिक उत्सव है। इस उत्सव को विजयवाड़ा में मनाया गया था। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है।
सरकारी योजनाएं	- मेघालय में हरित कार्यक्रम के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के 11वें संस्करण का आयोजन किया गया था। इस दौरान 'मेघालय राज्य में तीर्थाटन और विरासत पर्यटन के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास' नामक योजना के तहत मेघालय में कुछ पर्यटन स्थलों के विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया था। - तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान योजना (प्रसाद/ PRASHAD) योजना के तहत 46 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। साथ ही, 26 नवीन स्थलों की पहचान की गई है। - पर्यटन मंत्रालय ने अपनी स्वदेश दर्शन योजना को स्वदेश दर्शन 2.0 के तौर पर नए रूप में तैयार किया है। इसका उद्देश्य देश में जबाबदेह और सतत् पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन स्थलों के समेकित विकास का एक मजबूत ढांचा तैयार करना है। - रामसर स्थलों पर प्रकृति आधारित पर्यटन को मजबूत करने तथा अमृत धरोहर का कार्यान्वयन योजना के तहत स्थानीय पर्यटन सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। - अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना-2023 के तहत वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम शुरू किया गया।
पुरस्कार/ उपलब्धियां	पर्यटन मंत्रालय को इंटरनेशनल टूरिज्मस-बोरसे (ITB), बर्लिन 2023 में अंतर्राष्ट्रीय 'गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड 2023' में 'टीवी/ सिनेमा कमर्शियल इंटरनेशनल और कंट्री इंटरनेशनल' श्रेणी में गोल्डन व सिल्वर स्टार मिले हैं।

16. नागर विमानन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation)

उड़ान (UDAN) योजना	- उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान/ UDAN) योजना को 2016 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य इस्तेमाल से रहित और कम इस्तेमाल होने वाले हवाई अड्डों से क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाना तथा हवाई यात्रा को किफायती बनाना है। 2023 में क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS)³¹ में 60 नए मार्गों को शामिल किया गया है।
डिजी यात्रा	- यह हवाई अड्डों पर यात्रियों को संपर्क रहित व बाधा रहित डिजिटली वेरीफाई करने की एक परियोजना है। - डिजी यात्रा ऐप को अब तक 35 लाख से अधिक उपयोगकर्ता डाउनलोड कर चुके हैं। 91 लाख से अधिक यात्रियों ने डिजी यात्रा की सुविधा का लाभ उठाया है।
ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट	- ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा नीति को 2008 में अपनाया गया था। - इस तरह के 21 हवाई अड्डों के लिए 'सैद्धांतिक रूप से' मंजूरी दी गई है। इनमें से 12 हवाई अड्डे चालू हो गए हैं। 2023 में तीन ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे चालू हुए हैं।
ड्रोन	- ड्रोन नियम, 2021 के तहत सभी आवेदन फॉर्म डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन कर दिए गए हैं। - ड्रोन प्रमाणन योजना के तहत ड्रोन निर्माताओं द्वारा प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आसान हो गया है। - ड्रोन आयात नीति ने विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही, ड्रोन घटकों के आयात को शुल्क मुक्त कर दिया है। - ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022 ने ड्रोन पायलट लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। - ड्रोन और ड्रोन घटकों को PLI योजना में शामिल किया गया है।

³¹ Regional Connectivity Scheme

हरित ऊर्जा	66 हवाई अड्डे 100% हरित ऊर्जा द्वारा संचालित हैं। - भारत के दबाव और समान विचारधारा वाले देशों के समर्थन से कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (CORSIA) की बेसलाइन को 2019 के उत्सर्जन के 85% तक कम कर दिया गया है।
ऊंचाई के नियमों में संशोधन	- अवसंरचना का अधिकतम उपयोग करने के लिए हवाई अड्डों के आसपास की इमारतों की ऊंचाई के नियमों में संशोधन किया गया है। - अतीत में लगभग 40% हवाई क्षेत्र नागरिकों के उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं थे। इसके अलावा, 30% राष्ट्रीय हवाई क्षेत्र भारतीय वायु सेना (IAF) के नियंत्रण में था। इसमें से 30% को 'एयरस्पेस का लचीला उपयोग' के तहत ऊपरी हवाई क्षेत्र के रूप में माना गया है।
अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी	- भारत वर्तमान में 52 से अधिक देशों को सीधी कनेक्टिविटी और 100 से अधिक देशों को अप्रत्यक्ष मार्गों के माध्यम से कनेक्टिविटी प्रदान करता है। - मानव रहित विमान प्रणालियों तथा इनोवेटिव एयर मोबिलिटी में तकनीकी सहयोग के लिए DGCA और यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी (EASA) ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। - भारत ने 2022 में मालदीव और कनाडा के साथ तथा 2023 में न्यूजीलैंड के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट (आने-जाने के लिए असीमित उड़ानें) किया था। भारत ने अब तक 24 देशों के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट किया है।
कृषि उड़ान	- कृषि उड़ान योजना 2.0 (2021) पहाड़ी क्षेत्रों, उत्तर-पूर्वी राज्यों और जनजातीय क्षेत्रों से शीघ्र खराब होने वाले खाद्य उत्पादों के परिवहन पर केंद्रित है। - इस योजना के तहत देश के 58 हवाई अड्डे शामिल हैं। - यह योजना के तहत लैंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क आदि माफ किए गए हैं।

17. अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (Ministry of Minority Affairs)

प्रमुख पहलें	- सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के तहत 6 धर्मों के लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया है। ये हैं- मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। - प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (पीएम विकास/ PM VIKAS) योजना में पांच मौजूदा योजनाओं को शामिल किया गया है। इन योजनाओं में शामिल हैं- सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल। - प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम- यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसके तहत उन क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं का विकास किया जाता है, जहां 15 किलोमीटर के दायरे में अल्पसंख्यक आबादी की घनता 25 प्रतिशत से अधिक है। - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (NMDFC)³² की स्थापना कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत की गई है। यह अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है। - NMDFC ने ऋण लेखांकन प्रक्रियाओं (Loan Accounting Processes) को डिजिटल बनाने के लिए MILAN/ मिलान की शुरुआत की है। MILAN/ मिलान NMDFC के लिए अल्पसंख्यक ऋण लेखांकन सॉफ्टवेयर है।
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) संबंधी गतिविधियां	निम्नलिखित योजनाओं के लिए वेब पोर्टल बनाए गए हैं: - सीखो और कमाओ: अल्पसंख्यकों के कौशल विकास के लिए योजना। - नई रोशनी: अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं में नेतृत्व के विकास के लिए योजना।

³² National Minorities Development and Finance Corporation

	• नई मंजिल: अल्पसंख्यक समुदायों के लिए एक एकीकृत शिक्षा और आजीविका पहल। • उस्ताद (USTTAD): अल्पसंख्यक समुदायों की पारंपरिक कला और शिल्प को संरक्षित करने के लिए क्षमता निर्माण पहल में सहायता प्रदान करने की योजना। • उस्ताद (USTTAD): विकास के लिए पारंपरिक कला/ शिल्प में कौशल और प्रशिक्षण का उन्नयन करना। • नया सवेरा: अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित उम्मीदवारों/ छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग और संबद्ध योजनाएं। • प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम: अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में अवसंरचनात्मक विकास के लिए योजना। • NGO अनुदान पोर्टल: एग्रीगेटर और वेब पोर्टल। • जियो पारसी: पारसी समुदाय की जनसंख्या में आने वाली गिरावट को रोकने के लिए योजना।
--	---

18. खेल विभाग (युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय) {Department of Sports (Ministry of Youth Affairs And Sports)}

अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियां	• एशियन गेम्स (हांगकंग, चीन): कुल 107 पदक (28 स्वर्ण, 38 रजत व 41 कांस्य पदक)। • एशियन पैरा गेम्स: 29 स्वर्ण पदकों सहित कुल 111 पदक। • विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप: नीरज चोपड़ा ने अगस्त 2023 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता था। • फिडे (FIDE) विश्व कप: ग्रैंडमास्टर आर. प्रज्ञाननंद दूसरे स्थान पर रहे। • विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन गेम्स 2023 (बर्लिन): भारतीय दल ने कुल 202 पदक (76 स्वर्ण, 75 रजत और 51 कांस्य) जीते। • स्विस् ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप: सात्विकसाईराज रेड्डी और चिराग शेटी स्विस् ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी। • ISSF राइफल/ पिस्टल विश्व कप 2023 (भोपाल, भारत): मेजबान टीम ने 7 पदक (1 स्वर्ण, 1 रजत व 5 कांस्य) जीते और समग्र पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रही।
2023 में भारत द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाएं	• FIH ओडिशा हॉकी पुरुष विश्व कप, 2023 का आयोजन भुवनेश्वर और राउरकेला में किया गया था। • भारत में पहली बार MotoGP का आयोजन नोएडा में किया गया था। • IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। • अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) के 141वें सत्र का आयोजन मुंबई में किया गया था।
विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत किए गए आयोजन	• फिट इंडिया अभियान ○ तीसरा खेलो इंडिया क्विज़ का आयोजन किया गया था। ○ फिट (FIT) इंडिया स्वच्छता फ्रीडम रन 4.0 की शुरुआत मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम, नई दिल्ली में की गई थी। • खेलो इंडिया योजना ○ पहले, खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन दिल्ली में किया गया था। ○ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स (KIUG), 2022 का तीसरा संस्करण उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया था। ○ खेलो इंडिया महिला लीग की व्यापक सफलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2023 पर "खेलो इंडिया दस का दम" का आयोजन किया गया था।

	○ खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण अपर लेक, भोपाल (मध्य प्रदेश) में आयोजित किया गया था। ○ खेलो इंडिया शीतकालीन गेम्स का तीसरा संस्करण गुलमर्ग (जम्मू-कश्मीर) में आयोजित किया गया था।
डोपिंग-रोधी उपाय	• इसके लिए निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों (MoUs) पर हस्ताक्षर किए गए हैं- ○ युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, FSSAI तथा हैदराबाद स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (NIPER) ने MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। ○ राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (NADA) और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय डोपिंग रोधी संगठन (SARADO)³³ ने MoU पर हस्ताक्षर किए हैं। • नो योर मेडिसिन: यह एक वेब-पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन है। इसे स्वच्छ पोषक सप्लीमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे अभियान को मजबूत करने हेतु शुरू किया गया है।

19. संस्कृति मंत्रालय (Ministry of Culture)

आज़ादी का अमृत महोत्सव	• इस कार्यक्रम की शुरुआत भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के सम्मान और स्मरण में की गई है। • इसके तहत 'मेरी माटी मेरा देश' के अंतर्गत देश के हर भाग से एकत्रित की गई मिट्टी से अमृत वाटिका एवं अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया गया। • देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को सम्मानित करने के लिए 'मेरी माटी मेरा देश-माटी को नमन वीरों का वंदन' नामक एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की गई थी।
G-20 के आयोजन और अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध	• G-20 के संस्कृति कार्य-समूह की पहली, दूसरी व तीसरी बैठकें क्रमशः खजुराहो (मध्य प्रदेश), भुवनेश्वर (ओडिशा) और हम्पी (कर्नाटक) में आयोजित की गई थी। • G-20 संस्कृति कार्य-समूह की चौथी बैठक (वाराणसी) में G-20 के सभी देशों ने 'काशी कल्चर पाथवे' पर सहमति व्यक्त की। • मिस्र, कोलंबिया, मॉरीशस, इटली, बेलारूस आदि देशों के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम (CEP)³⁴ पर हस्ताक्षर किए गए। • पुरावशेषों की पुनर्प्राप्ति: 1976 से नवंबर 2023 तक विभिन्न देशों से कुल 357 पुरावशेष वापस लाए गए हैं। • संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल होने वाले स्थल	• 45वीं विश्व धरोहर समिति (2023) की बैठक रियाद (सऊदी अरब) में आयोजित की गई थी। • भारत के शांति निकेतन और होयसल शासकों द्वारा निर्मित मंदिरों (होयसल पवित्र मंदिर समूह) को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। • यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या की दृष्टि से भारत अब दुनिया में छठे स्थान पर है। भारत में कुल 42 (सांस्कृतिक-34, प्राकृतिक-7 और मिश्रित-1) विश्व धरोहर स्थल हैं।

³³ South Asia Regional Anti-Doping Organization

³⁴ Cultural Exchange Program

	• 2023 में ग्वालियर और कोझिकोड को क्रमशः संगीत व साहित्य के रचनात्मक शहरों के रूप में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल किया गया था। • गुजरात के 'गरबा' नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है।
महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन	• महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रमों का उद्घाटन किया गया था। • जम्मू और कश्मीर की जीवंत सांस्कृतिक परंपराओं का जश्न मनाने के लिए 'वितस्ता उत्सव' मनाया गया था। • भारत का सबसे बड़ा लोक और जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रम, 'उत्कर्ष' भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। • रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के अवसर पर जबलपुर में 'वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान' का भूमि पूजन किया गया था। • मीरा बाई की 525वीं जयंती के अवसर पर 525 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया था। साथ ही, मीरा बाई के जीवन पर आधारित डाक टिकट भी जारी किया गया। • गीता प्रेस, गोरखपुर को 2021 के गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया।